



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2017/फाल्गुन 24, 1938

No. 58]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2017/PHALGUNA 24, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2017

(अंतिम जांच परिणाम)

(पाटन-रोधी जांच)

विषय : माननीय सेस्टेट के दिनांक 16.09.2016 के आदेश द्वारा वापस की गई रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन" (पीटीएफई) के आयात संबंधी पाटन-रोधी जांच।

सं.15/2/2015-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली भी कहा गया है) और माननीय सेस्टेट के दिनांक 16.09.2016 के आदेश संख्या 53592/2016 को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

मेसर्स गुजरात फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई निर्णायक समीक्षा जांच संबंधी याचिका के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को अंतिम जांच परिणाम जारी किया था जिसमें उन्होंने रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन" (पीटीएफई) के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। राजस्व विभाग ने दिनांक 6 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटन-रोधी शुल्क लगाया था।

क्षति रहित कीमत के निर्धारण के मुद्दे पर घरेलू उद्योग की अपील के आधार पर माननीय सेस्टेट ने इस मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए वापस भेज दिया है कि वे इसका निर्धारण पूरा करें और सरकार के सक्षम प्राधिकारी

को अंतिम जांच परिणाम दें ताकि वे उपरोक्त आदेश के पैरा 9 में दिए गए निर्देश के अनुसार आदेश की तारीख 16 सितंबर, 2016 से छः महीने की अवधि के भीतर जैसा भी उचित समझें कार्रवाई करें। इसलिए संशोधित अंतिम जांच परिणाम 15 मार्च, 2017 तक पूरा किया जाना है।

घरेलू उद्योग ने यह प्रतिवेदन किया है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत (एनआईपी) कम है और यह पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार असंगत है तथा संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए केप्टिवली प्रयुक्त इनपुट का मूल्यांकन करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले आधार के भी विपरीत है। चूंकि सुसंगत पद्धति के अनुसार प्राधिकारी ऐसी इनपुट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाली सम्पत्ति के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ जोड़ते हैं, यदि इन्हें उत्पादन की लागत में अंतरित किया जाता है।

घरेलू उद्योग ने न्यायाधिकरण के समक्ष यह निवेदन किया है कि याचिकादाता ने जांच के दौरान इन विभिन्न केप्टिव इनपुट के उत्पादन की लागत को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था।

सेस्टेट ने यह पाया है कि निर्धारण करने का केवल बिन्दु याचिकादाता द्वारा संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करते समय केप्टिवली उत्पादित और उपभुक्त की गई बड़ी मात्रा में इनपुट पर विचार करते हुए क्षति रहित कीमत का आकलन करते समय प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति के पारिशुद्धता का है। न्यायाधिकरण ने आगे यह भी पाया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षति रहित कीमत का आकलन करने के लिए केप्टिवली इनपुट के उत्पादन में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ को भी जोड़ते रहे हैं।

साथ ही सेस्टेट ने यह भी पाया है कि प्राधिकारी ने पद्धति में अचानक ऐसे परिवर्तन किए जाने के लिए कोई कारण नहीं बताया है और न ही केप्टिवली उपभुक्त इनपुट के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रावधान (नियम 8) को अपनाए जाने के लिए भी कोई कारण नहीं बताया है। पाटन-रोधी नियमावली अथवा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कि ऐसे नियम को लागू और पाटन-रोधी जांच में क्षति रहित कीमत का परिकलन करने का अधिदेश देता है। ऐसे सांचे में सेस्टेट ने यह पाया है कि वर्तमान मामले में निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत गलत थी जहां तक कि यह नियोजित पूंजी पर लाभ/प्रतिलाभ के विशिष्ट संदर्भ में केप्टिवली उपभुक्त की गई वस्तुओं के निरूपण से संबंधित है।

इसलिए सेस्टेट ने इस कारणवश प्राधिकारी के दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के अंतिम जांच परिणाम को एक तरफ रख दिया है और प्राधिकारी को निदेश दिया है कि लागू कानूनी प्रावधान के अनुसार परिणाम देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को उचित अवसर प्रदान करने के बाद नए सिरे से मामले की जांच की जाए। विशिष्ट संदर्भ में केप्टिवली उपभुक्त की गई वस्तुओं के निरूपण से कीमत का आकलन करने के कारण को रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। उसके बाद वर्तमान मामले में लगाए जाने वाले पाटन मार्जिन और पाटन-रोधी शुल्कों का निर्धारण विधि के अनुसार किया जा सकता है।

ख. अपनाई गई क्रिया-विधि

- (1) पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 6 (6) और सेस्टेट के आदेश दिनांक 16 सितंबर, 2016 के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 2 दिसंबर, 2016 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था। इस मौखिक सुनवाई में जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त किए थे, उन्हें सलाह दी गई थी कि वे अपने विचारों को अन्य प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के साथ ऐसे विचारों को पारस्परिक रूप से आदान-प्रदान करने के लिए लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें ताकि अन्य पक्षकारों द्वारा उनके उत्तर दिए जा सकें।
- (2) याचिकादाता ने रणजीत नगर में उत्पादित आर-22 के उत्पादन की लागत और अपने उत्पादन के लिए नियोजित निबल अचल सम्पत्तियों के व्यौरों के साथ दिनांक 11 जनवरी, 2017 के पत्र द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के परिकलनों में गलती हो सकती है और इसलिए उसकी समीक्षा की जा रही है। आगे यह भी बताया गया है कि नियमावली में ऐसी अपेक्षा है कि प्राधिकारी को केप्टिव इनपुट के उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार करना चाहिए और न कि केप्टिव इनपुट की क्षति रहित कीमत पर।
- (3) याचिकादाता द्वारा डीजीएडी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को 23 फरवरी, 2017 को सत्यापित किया गया था।
- (4) इस अंतिम जांच परिणाम में एक हितबद्ध पक्षकार/किसी अन्य पक्षकार द्वारा *** सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा समझा गया है।

- (5) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा 8 मार्च, 2017 को संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को अत्यावश्यक तथ्यों का प्रकटन कर दिया गया था। उनसे अनुरोध किया गया था कि वे उन पर अपनी टिप्पणियों 14 मार्च, 2017 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। प्रकटन विवरण पर प्राप्त हुई टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक समझा गया है, इस अंतिम परिणाम में विचार किया गया है।
- (6) विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सभी अन्य मानदंड घरेलू उद्योग का क्षेत्र, अवधि, पाटन और क्षति का मूल्यांकन वही रहते हैं। जांच परिणाम केवल एनआईपी के निर्धारण तक सीमित हैं। जैसा कि माननीय सेस्टेट द्वारा दी गई रिमांड केवल एनआईपी के पुनर्ग्रहण के मुद्दे के संबंध में हैं।

ग. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

(क). ओएओ हेलो पोलिमेर ओजेएससी, रूसी परिसंच के प्रतिनिधि निर्यातक मेसर्स वर्ल्ड ट्रेड कंसलटेंट्स एंड एडवोकेट्स द्वारा किए गए निवेदन।

- (1) माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई अपील इस अवधारणा पर आधारित है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निरंतर केप्टिवली उत्पादित कच्चे माल की उत्पादन की लागत को ही अपनाया है और तैयार उत्पाद के लिए क्षति रहित कीमत का आकलन करने के लिए ऐसे कच्चे माल में नियोजित पूंजी पर 22% का प्रतिलाभ जोड़ा है, लेकिन अपील के अंतर्गत अंतिम जांच परिणाम में क्षति रहित कीमत का आकलन उस आधार पर नहीं किया गया है। इस तर्क के आधार पर माननीय न्यायाधिकरण ने ऐसे अंतिम जांच परिणाम को एक तरफ रख दिया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी से कहा है कि वे समग्र मुद्दे पर पुनर्विचार करें। घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह सुसंगत पद्धति रही है कि वे क्षति रहित कीमत का आकलन करने के लिए केप्टिवली उत्पादित कच्चे माल के उत्पादन में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ को भी जोड़ते रहे हैं, भ्रामक प्रतीत होता है तथा तथ्यों पर आधारित नहीं है। वास्तव में रूस से पीटीएफई के संबंध में विगत निर्णायक समीक्षा जांच में दिनांक 26 फरवरी, 2010 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 15/30/2008-डीजीएडी में यह निष्कर्ष दिया गया है कि पैरा 23 से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पीटीएफई की क्षति रहित कीमत का आकलन करने के लिए केप्टिवली उत्पादित और उपभुक्त किए गए कच्चे माल के संबंध में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ को जोड़ने की पद्धति को नहीं अपनाया है। घरेलू उद्योग ने माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसा गलत निवेदन किया है कि तैयार उत्पाद के उत्पादन की लागत के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ को जोड़ने की निर्दिष्ट प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति रही है। वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के आर-22 की कीमत के अंतरण के दावे, वर्ष 2010 में की गई विगत निर्णायक समीक्षा जांच में उसके दावों से पूर्णतया भिन्न हैं। इसलिए यह बताया गया है कि घरेलू उद्योग को विगत निर्णायक समीक्षा जांच में आर-22 पर नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ प्रदान करने का घरेलू उद्योग का दावा झूठा है।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी भिन्न स्थान पर उत्पादित कच्चे माल की केप्टिव खपत और केप्टिव खपत के लिए उसका अन्य स्थान पर अंतरण और उसी स्थान पर उत्पादित और उपभुक्त किए गए कच्चे माल के बीच के अंतर को विशिष्ट रूप से स्पष्ट करेंगे।
- (3) केप्टिव खपत का वर्णन केप्टिव प्रयुक्त के लिए उत्पादन की लागत पर लागत लेखाकरण मानक (सीएस-4) की दिशा-निर्देशी टिप्पणी के अध्याय 1 में किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी केप्टिव को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, नामतः-
 - (क) एक फैक्टरी के परिसर में उत्पादित और केप्टिव खपत के लिए प्रयुक्त कच्चा माल और
 - (ख) उसी कंपनी द्वारा भिन्न फैक्टरी/स्थान में उत्पादित और भिन्न उत्पाद का आगे उत्पादन करने के लिए केप्टिव खपत करने के लिए अन्य फैक्टरी को अंतरित किया गया कच्चा माल।
- (4) संस्थान ने दोनों किस्मों की केप्टिव खपत के लिए भिन्न निरूपण निर्धारित किया है। यदि कच्चे माल का उपयोग उसी फैक्टरी के परिसर में विनिर्मित किया जाता है, जो उसका मूल्यांकन उसकी लागत के आधार पर किया जाए और यदि कच्चे माल को फैक्टरी के परिसर से दूसरी फैक्टरी के परिसर में केप्टिव खपत करने के लिए अंतरित किया

जाता है तो उसका मूल्यांकन सीएएस-4 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुपालन द्वारा किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में आर-22 का केप्टिवली उत्पादन, याचिकादाता मेसर्स गुजरात फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड के रणजीत नगर स्थित संयंत्र में किया गया था और उसे बाद में पीटीएफई का निमार्ण करने के लिए केप्टिव खपत के लिए दहेज संयंत्र को अंतरित कर दिया गया था।

- (5) ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के लिए जिन्हें उत्पादन की लागत पर केप्टिवली खपत के लिए नहीं बेचा गया है, उत्पादन की लागत का निर्धारण भारत सरकार, वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग के दिनांक 13 फरवरी, 2003 के परिपत्र) द्वारा सीएएस-4 के अनुसार किया जाता है। स्वःविनिर्मित मदों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी केप्टिव खपत के लिए उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के सिद्धांतों के अध्याय-3 के अनुसार किया जाना चाहिए परिपत्र संख्या 692/08/2003-सीएक्स, दिनांक 13 फरवरी, 2003, एफ संख्या 6/29/2002-सीएक्स-1, वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय, राजस्व विभाग में यह बताया गया है कि अब से केप्टिवली उपभुक्त वस्तुओं के उत्पादन की लागत का निर्धारण सख्ती से सीएएस-4 के अनुसार किया जाएगा।
- (6) केप्टिवली उपभुक्त वस्तुओं के उत्पादन की लागत का निर्धारण सीएएस-4 के अनुसार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे बनाम मेसर्स केडबरी इंडिया लिमिटेड के मामले संख्या वर्ष 2001 की अपील (सिविल) 2947-2948 में लिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 1.8.2006 के निर्णय के अनुसार किया जाएगा।
- (7) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार मेसर्स गुजरात फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड द्वारा पीटीएफई विनिर्मित करने के लिए केप्टिवली उपभुक्त आर-22 की अंतर कीमत का सही आकलन किया है।

(ख). घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

- (1) याचिकादाता का यह विचार है कि वर्तमान मामले में मौखिक सुनवाई की स्वीकृति देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सेस्टेट ने वर्तमान मामले में मौखिक सुनवाई का संचालन करने का निर्देश नहीं दिया है। जब सेस्टेट ने ऐसी कामना की थी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करें, तो सेस्टेट ने उसके बारे में विशेष रूप से बताया था। रबड रसायनों के मामले में जिसमें सेस्टेट ने मामले को वापस निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेज दिया था, सेस्टेट ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को विशेष रूप से यह निर्देश दिया था कि वे हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करें।
- (2) वर्तमान मामले में सीमित मुद्दा केवल क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने से संबंधित है। याचिकादाता घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया था कि वे उत्पादन की उसकी लागत पर केप्टिव इनपुट पर विचार करें और नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ को जोड़ें। सेस्टेट ने यह माना है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ जोड़ने की आवश्यकता है।
- (3) वर्तमान मामले में विचार किए जाने के लिए केवल सीमित मुद्दा नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ जोड़ कर क्षति रहित कीमत को संशोधित करने का है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए सभी अन्य पहलुओं को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पहले से ही स्थिर कर दिया गया है तथा घरेलू उद्योग अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उसके बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की है।
- (4) मामला वापस लेने संबंधी कार्यवाई में निर्दिष्ट प्राधिकारी को नए सिरे से निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को पक्षकार द्वारा उठाए गए और सेस्टेट द्वारा निर्णीत मुद्दे का ही समाधान करने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग द्वारा उठाया गया मुद्दा यह था कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण केप्टिव इनपुट में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ जोड़ कर किया जाना चाहिए। इस चरण में क्षति रहित कीमत के किसी भी पहलु पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
- (5) सेस्टेट ने यह माना है कि वर्तमान प्रयोजनार्थ उत्पाद शुल्क का मूल्यांकन प्रासंगिक नहीं है।
- (6) एक हितबद्ध पक्षकार के इस तर्क के संबंध में कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माननीय नयायाधिकरण के समक्ष निराधार यह निवेदन किया है कि तैयार उत्पादों के लिए क्षति रहित कीमत का आकलन करने के लिए केप्टिवली उत्पादित कच्चे माल के उत्पादन की लागत में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ जोड़ने की निर्दिष्ट प्राधिकारी की एक

सुसंगत पद्धति रही है, उसकी परिशुद्धता को अथवा सेस्टेट के निर्णय को चुनौती देने के समान है। सबसे पहले पक्षकार प्रतिवादी बनाए जाने के बावजूद भी सेस्टेट के समक्ष अपील में भाग लेने का इच्छुक नहीं होता है। दूसरे वर्तमान कार्रवाईयों के कार्य-क्षेत्र में सेस्टेट के आदेश की परिशुद्धता अथवा अन्यथा समीक्षा करना शामिल नहीं है। यदि कोई पक्षकार सेस्टेट के आदेश से सहमत नहीं है, तो वह उच्चतर न्यायालय में उसके खिलाफ अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी को सेस्टेट के आदेश की परिशुद्धता अथवा अन्यथा उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को सेस्टेट के आदेश को ध्यान में रखते हुए क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने की आवश्यकता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उत्पादन की लागत पर आर-22 पर विचार करेंगे और उसमें 22% प्रतिलाभ को जोड़ेंगे। बहुत सीमित मुद्दे को छोड़ कर जिसमें (क) आर-22 मूल्य में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ को जोड़ना, (ख) उसके बाद क्षति रहित कीमत का निर्धारण करना और (ग) संशोधित क्षति मार्जिन का परिकलन करना शामिल है, वर्तमान मामले को वापस करने की कार्रवाईयों में दुबारा कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को सेस्टेट के आदेश की उपयुक्तता अथवा अन्यथा के संबंध में किसी भी तर्क पर विचार नहीं करना है।

(7) घरेलू उद्योग का निवेदन है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सेस्टेट के आदेश की परिशुद्धता अथवा अन्यथा उसको चुनौती देने के लिए वह पक्षकार स्वतंत्र नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों की कोई अधिकारिता नहीं है क्योंकि वह सेस्टेट के समक्ष घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई अपील को चुनौती देने के लिए पक्षकारों के लिए और अपने हित और/अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश के बचाव में स्वतंत्र था। अब सेस्टेट ने एक आदेश पारित कर दिया है कि हितबद्ध पक्षकार सेस्टेट के निर्णय पर परामर्श नहीं कर सकते हैं और सेस्टेट के आदेश की परिशुद्धता अथवा अन्यथा उस संबंध में विवाद कर सकते हैं।

(8) (सीएस-4) और एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा उल्लिखित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में निवेदन है कि ये वर्तमान जांच से पूर्णतया प्रासंगिक नहीं हैं। वर्तमान प्रयोजनार्थ जैसा कि सेस्टेट ने माना है, सरकार ने एक कार्य प्रणाली बनाई है और एक विधि शुरू की है तथा उसे लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस विधि में ऐसा उल्लेख नहीं है कि केप्टिव इनपुट को निरपवाद रूप से उत्पादन की उसकी लागत पर विचार किया जाएगा। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संदर्भित सभी निर्णय उत्पाद शुल्क के मामलों से संबंधित हैं, जिनकी वर्तमान मुद्दे से कोई प्रासंगिकता नहीं है। वास्तव में सेस्टेट ने पहले से ही यह माना है कि वर्तमान प्रयोजनार्थ उत्पाद शुल्क का मूल्यांकन और उस पर लागू कार्य प्रणाली समग्र रूप से अप्रासंगिक हैं।

क. इस मुद्दे पर कि निर्दिष्ट प्राधिकारी विभिन्न स्थल में उत्पादित कच्चे माल की केप्टिव खपत और केप्टिव खपत के लिए अन्य स्थल पर अंतरित कच्चे माल तथा उसी स्थान पर उत्पादित और प्रयुक्त कच्चे माल के बीच अंतर है, सेस्टेट के आदेश के खिलाफ तर्क देने का पक्षकारों का विषय नहीं है। सेस्टेट के आदेश का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि दो भिन्न कार्य-प्रणालियां समाविष्ट हैं। इसके विपरीत सेस्टेट ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि उत्पाद शुल्क की कार्य प्रणाली को वर्तमान प्रयोजनार्थ नहीं माना जाएगा।

(9) यदि केप्टिव इनपुट में 22% जोड़ने और क्षति रहित कीमत में उचित रूप से संशोधन करने तथा संशोधित/आशोधित क्षति रहित कीमत पर उपयुक्त रूप से विचार करके क्षति मार्जिन में संशोधन किया जाता है तथा पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन करने/बढ़ाने की सिफारिश की जाती है, तो सेस्टेट के आदेशों के आलोक में तथा याचिकादाता द्वारा पहले से प्रदान की गई सूचना के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को सेस्टेट के आदेश की परिशुद्धता अथवा अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग). रूस के परिसंघ के आर्थिक विभाग के मंत्रालय द्वारा किए गए निवेदन

(1) अंतिम जांच परिणाम का प्रार्थित संशोधन, विश्व व्यापार संगठन के टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार 1994 (पाटन-रोधी करार) के अनुच्छेद-4 के क्रियान्वयन के करार और महानिदेशक के निष्कर्षों के पूर्णतया अनुपालन से हो और यह संशोधन की प्रक्रिया में क्षति रहित कीमत के परिकलन के ढांचे से बाहर हो।

- (2) सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण नियमावली, 1982 के अनुच्छेद 10 के अनुसार और सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाएं अपील न्यायाधिकरण के ढांचे के अंतर्गत महानिदेशालय द्वारा किए गए पाटन मार्जिन परिकलन और क्षति मार्जिन में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।
- (3) क्षति रहित कीमत का परिकलन स्वतः अत्यावश्यक नहीं है और इसे पाटन-रोधी करार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाए। पाटन-रोधी उपाय लागू करने की सामान्य पद्धति से अधिकतर मामलों में जांच की कार्रवाई के दौरान निर्धारित क्षति मार्जिन के समनुरूप शुल्क की दर का पता चलता है।
- (4) विश्व व्यापार संगठन की नियमावली के अनुसार पाटन-रोधी जांच के ढांचे में क्षति रहित कीमत का परिकलन करने का उद्देश्य निम्नतर शुल्क वसूल करने का है, ताकि पाटन-रोधी शुल्क को उस दर पर लागू किया जाए, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो। यह कार्य-प्रणाली राज्य के आर्थिक हितों की सुरक्षा करने का एक तंत्र है, जिसे इस मामले में भारतीय घरेलू उद्योग की क्षति और आयातित वस्तुओं के उपभोक्ताओं के संभावित परिणामों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल समझा गया है। ऐसे परिकलन और विश्लेषण का संचालन, पाटन-रोधी जांच का संचालन करने के लिए प्राधिकृत सक्षम निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (5) पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत यह निर्णय कि क्या ऐसे मामले में पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए अथवा नहीं, जिनमें लगाए जाने वाले पाटन-रोधी शुल्क की राशि पाटन के पूरे अथवा कम मार्जिन पर होगी, के निर्णय आयातक सदस्य के प्राधिकारियों द्वारा लिए जाएं। यह बांछनीय है कि सभी सदस्यों के क्षेत्र में ऐसे शुल्क लगाए जाने अनुमत हों और यदि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए कमतर शुल्क पर्याप्त हों तो मार्जिन से कमतर शुल्क लगाए जाएं।
- (6) सक्षम प्राधिकारी के रूप में पाटन-रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को आयातकों और उत्पादकों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए क्षति रहित कीमत के परिकलन प्रक्रिया का उपयोग करके पाटन-रोधी शुल्क की दर से संबंधित निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया जाए।
- (7) इसके अतिरिक्त सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाएं अपील न्यायाधिकरण के अनुसार याचिकादाता का विचार है कि महानिदेशक द्वारा निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत सही है, जब कि विगत जांच के दौरान इसके लिए उचित कार्य-प्रणाली से भिन्न अनुचित कार्य-प्रणाली प्रयुक्त की गई थी।
- (8) इसके बावजूद भारतीय पाटन-रोधी विधान में एक परिशिष्ट के रूप में क्षति रहित कीमत का परिकलन करने की कार्य-प्रणाली निहित है, जिसमें सक्षम निकाय को एक अथवा अन्य कार्य-प्रणाली प्रयुक्त करने के दायित्व का उल्लेख नहीं है। इसलिए भारतीय पाटन-रोधी व्यवस्था में महानिदेशक को निम्नतर शुल्क के नियम के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षति रहित कीमत का परिकलन करने के लिए एक अथवा अन्य कार्य-प्रणाली का चयन करने का प्रावधान नहीं है।
- (9) हम सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाएं अपील न्यायाधिकरण के विवरण के अनुच्छेद 8 में निर्धारित पाटन-रोधी शुल्क की दर का वर्णन करने के लिए भारतीय पक्ष के इरादों के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और यह कि रूस के निर्यातक पाटन-रोधी शुल्क की समीक्षा की कार्रवाई में सक्षम निकाय द्वारा चुनी गई (याचिकादाता के दृष्टिकोण से) गलत कार्य-प्रणाली के किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे।
- (10) याचिकादाता के दावे के फलस्वरूप भारतीय पक्ष द्वारा पाटन-रोधी विधान का उल्लंघन हो सकता है।
- (11) यदि क्षति रहित कीमत में इस प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है, तो ऐसा निम्नतर शुल्क नियम को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। तब संशोधन की कार्रवाई के दौरान रूस की कंपनियों के लिए परिकलित की गई कम कीमत पर बिक्री और कीमत में कटौती की राशि का संकलन किया जाए।

घ. मामले के तथ्य और एन आई पी की पुनः जांच

- (1) याचिकादाता मेसर्स गुजरात फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड के दो संयंत्र हैं, जिनमें से एक संयंत्र रणजीत नगर में और दूसरा संयंत्र दहेज में स्थापित है। जांच अवधि के दौरान एक प्रमुख इनपुट आर-22 है, जो कि रणजीत नगर में उत्पादित की

- गई थी और टीएफई का उत्पादन करने के लिए उसका प्रयोग दहेज संयंत्र में किया गया था। टीएफई संबद्ध वस्तुओं पीटीएफई का उत्पादन करने के लिए प्रमुख कच्चा माल है। ये दोनों संयंत्र बहु-उत्पाद और बहु-प्रक्रिया वाले संयंत्र हैं।
- (2) याचिकादाता ने मूल निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान रणजीत नगर के अपने संयंत्र में आर-22 के उत्पादन के लिए नियोजित सम्पत्तियों के ब्यौरों सहित उत्पादन की लागत प्रदान नहीं की थी। साथ ही मौके पर की गई जांच में भी कंपनी ने ऐसे आंकड़े प्रदान नहीं किए थे। चूंकि याचिकादाता ने आर-22 की कीमत का दावा, उसके उत्पादन की लागत सहित नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ के आधार पर नहीं किया था, इसलिए उनकी लेखा बहियों में उल्लिखित अनुसार आर-22 मूल्य पर विचार किया गया था।
 - (3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद कर लगाए जाने वाली वस्तुओं का निर्धारण) नियम, 2000 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि जहां उत्पाद शुल्क लगाए जाने वाली योग्य वस्तुओं को करदाता द्वारा बेचा जाता है, लेकिन उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से उनका उपयोग अन्य वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्माण करने में किया जाता है, तो उनका मूल्य ऐसी वस्तुओं के उत्पादन अथवा निर्माण की लागत से एक सौ दस प्रतिशत होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी सीएएस-4 दिशा-निर्देशी टिप्पणी में बताया गया है कि यह मानक, लागत शीट में केप्टिव प्रयुक्त, प्रस्तुतीकरण और प्रकटन के लिए उत्पाद कर लगाए जाने योग्य संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए सिद्धांतों और विधियों का निर्धारण करता है। इस दिशा-निर्देशी टिप्पणी में यह भी बताया गया है कि "केप्टिवली उपभुक्त की गई वस्तुओं की उत्पादन लागत का वहन कड़ाई से सीएएस-4 के अनुसार किया जाए"। यह मानक उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है, जिस पर लाभ का 10% घटक को करदाता के अन्य यूनिट द्वारा प्रयुक्त करने के प्रयोजनार्थ हटाई गई इनपुट के बीजक मूल्य के प्रयोजनार्थ मूल्यांकन करने योग्य मूल्य का आक्कलन करने के लिए जोड़ा जाएगा।
 - (4) चूंकि याचिकादाता ने आर-22 की कीमत का दावा नहीं किया था और उसने न तो याचिका दायर करते समय और न ही मौके पर जांच करने के समय आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत किए थे, इसलिए यह समझा गया था कि कंपनी आर-22 की अंतरण कीमत का निर्धारण करने के लिए सीएएस-4 का और केन्द्रीय उत्पाद मूल्यांकन नियमावली अनुपालन कर रही है। प्राधिकारी स्वतः केप्टिव इनपुट आर-22 के उत्पादन की लागत और नियोजित सम्पत्तियों के मूल्य का अनुमान नहीं लगा सकते थे और उन्हें लेखा बहियों पर विश्वास करना पड़ा था। अनुबंध-3 के अनुच्छेद (3) में ऐसा प्रावधान है, जिसके अनुसार घरेलू उद्योग का सहभागी बनने वाले उत्पादक के संबंध में जांच अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना अथवा आंकड़ों को ध्यान में रख कर क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया जा सकता है और उत्पादन की लागत में वास्तविक संख्या शामिल है, जैसा कि लेखाओं की लेखा-परीक्षित बहियों में दर्शाया जाता है न कि भावात्मक अथवा काल्पनिक संख्या में। इसमें यह नहीं बताया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा लागत के कोई आंकड़े प्रदान किए बिना प्राधिकारी को स्वतः घरेलू उद्योग के सहभागी के उत्पादन की लागत की संरचना करनी चाहिए।
 - (5) इस मुद्दे को याचिकादाता के प्रतिनिधि द्वारा पहली बार दिनांक 31.03.2016 के पत्र में उठाया गया था जिसमें उसने रणजीत नगर में आर-22 का उत्पादन करने के लिए नियोजित विंड पावर सम्पत्तियों पर अतिरिक्त प्रतिलाभ देने का अनुरोध किया था। घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि ने विशेष रूप से यह बताया था कि एमडीसी की लागत का निर्धारण करने की समीक्षा करने के साथ-साथ उसी समय डीजीएडी में कंपनी के अन्य मामले पर भी समीक्षा की जा रही थी, जिसमें याचिकादाता ने पाया कि उसने गलती से अन्य स्थान पर केप्टिवली इनपुट के उत्पादन के लिए नियोजित पूंजी के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की थी।
 - (6) याचिकादाता को आर-22 के उत्पादन की लागत के संबंध में विधिवत प्रमाणों से युक्त और प्रमाणित किए गए ब्यौरों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। इसलिए विधिवत प्रमाणों से युक्त और प्रमाणित लागत संबंधी सूचना के उपलब्ध नहीं होने पर प्राधिकारी के लिए उसके दावे की जांच किए बिना उस पर विचार करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त कंपनी के रणजीत नगर स्थित संयंत्र पर आर-22 के उत्पादन के लिए नियोजित पूंजी पर 22% के लाभ के बदले (यह मानते हुए कि कंपनी ने उत्पाद शुल्क मूल्यांकन नियमावली का उल्लंघन नहीं किया है) कंपनी को ***% लाभ पहले से ही अंतर-निर्मित प्राप्त था। उत्पाद शुल्क मूल्यांकन

नियमावली के अनुसार कीमत अंतरण को स्वीकार करने के लिए डीजीएडी की इस पद्धति को इस मामले सहित विगत अनेक मामलों में पहले से ही अपनाया गया है और विगत में किसी भी मामले में याचिकादाता अथवा घरेलू उद्योग ने इस पद्धति का मुद्दा पहले कभी नहीं उठाया है और न ही उसको चुनौती दी है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीटीएफई के विगत मामलों में याचिकादाता ने निम्नोक्त के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है:—

- रूस से आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच (एफ संख्या 15/30/2008-डीजीएडी) - प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2010 के अंतिम जांच परिणाम के पैरा 23 (घ) में यह आधार लिया गया था कि ".....चूंकि घरेलू उद्योग आर-22 का कैप्टिवली उत्पादन कर रहा था, प्राधिकारी को आर-22 की बाजार कीमत पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए आर-22 के उत्पादन की लागत, पीटीएफई की प्रासंगिक नहीं हो सकती है"।
- चीन से आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच (एफ संख्या 15/8/2010-डीजीएडी) - प्राधिकारी ने 25 जुलाई, 2011 के अंतिम जांच परिणाम के पैरा 29 (3) में यह आधार लिया था कि "जीएपीपी के आधार पर तथा कंपनी द्वारा बना कर रखे गए रिकार्ड के आधार आर-22 की कीमत के अंतरण के मुद्दे के संबंध में....."।
- इसी प्रकार का आधार एमटीआर के परिणाम के पैरा 29 (ग) में लिया गया था जिसमें ".....प्राधिकारी को आर-22 की बाजार कीमत पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए आर-22 के उत्पादन की लागत, पीटीएफई की प्रासंगिक नहीं हो सकती है"।

ड. प्रकटन के उत्तर

प्रकटन के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) प्रकटन के विवरण से याचिकादाता प्राधिकारी से अपनाई गई धनराशि को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है कि इसे स्वीकार किया गया है अथवा नहीं। संपूर्ण प्रकटन न होने की स्थिति में याचिकादाता प्राधिकारी द्वारा किए गए परिकलनों, संशोधित क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली स्वीकार किए गए लागतों और नियोजित पूंजी के तत्वों तथा अस्वीकृत किए गए लागत और नियोजितपूंजी के तत्वों को पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहा है।
- (2) प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच के समय आर-22 के उत्पादन की लागत को पहले सत्यापित किया था और उसमें संशोधन कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि प्राधिकारी ने आर-22 के उत्पादन की लागत को दो विभिन्न तरीकों से विचार किया गया है, एक निर्णायक समीक्षा जांच के समय और दूसरा अब। चूंकि आर-22 के उत्पादन की लागत को निर्णायक समीक्षा जांच के समय पहले से सत्यापित किया गया था, उसे दोबारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस समय किए गए आर-22 के उत्पादन की लागत में संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है।
- (3) याचिकादाता ने डी जी ए डी द्वारा मांग की गई प्रत्येक सूचना प्रदान की है तथा वर्तमान प्रकटन विवरण से पहले याचिकादाता को ऐसा कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि याचिकादाता ने कुछ सूचना प्रदान नहीं की है अथवा मांगा गया कोई स्पष्टीकरण लिखित रूप में नहीं दिया है। याचिकादाता का यह विचार है कि यह मानना अनुचित है कि सत्यापन के समय कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका था।
- (4) एनएफए को खोलने और बंद करने के समय उसका औसत निकाले बिना क्लोरोफार्म के लिए एनएफए किया गया है। केवल खुले हुए एनएफए के आंकड़ों पर विचार किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बंद एनएफए की अनदेखी की गई है। यदि ऐसा है तो याचिकादाता का यह निवेदन है कि प्राधिकारी की यह सुसंगत पद्धति रही है कि वे एनएफए के खोलने और बंद करने का सामान्य औसत निकाल करके एनएफए की औसत पर विचार करते हैं।
- (5) याचिकादाता का निवेदन है कि निर्धारित की गई क्षतिरहित कीमत में दहेज में नियोजित पूंजी, जोकि *** रुपए है, को शामिल नहीं किया जाता है जोकि आर-22 के उत्पादन में नियोजित पूंजी होती है और दहेज में सभी उसकी कैप्टिव इनपुट होती है। चूंकि आर-22 के कुछ अंश का दहेज में उत्पादन किया गया है और उसकी खपत की गई है,

इसलिए उस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह राशि दहेज संयंत्र की एनएफए अनुसूची में स्पष्ट रूप से दर्शायी गई है। इसके अतिरिक्त, इस राशि को एम डी सी के मामले में प्रस्तुत की गई सूचना में भी स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है।

- (6) *** रुपए प्रति यूनिट के अनुसार विंड मिल पावर की दर को ध्यान में रखते हुए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है, यह आंकड़ा सही नहीं है। *** रुपए का आंकड़ा मिहाड विंड मिल संयंत्र में विद्युत के उत्पादन की लागत है और इसे रणजीत नगर की लेखा बहियों में दर्शाया गया है। इस समस्त विद्युत की खपत दहेज में की गई है। तथापि, कंपनी द्वारा यह विद्युत सरकार को मिहाड में *** रुपए की दर से दी गई है और दहेज में इसे *** रुपए प्रति यूनिट की दर से लाया गया है (***) रुपए अंतरित लागत और *** रुपए व्हीलिंग प्रभाग)। कंपनी ने इस विद्युत के लिए दहेज को *** रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया है, जिसे दहेज की लेखा बहियों में दर्शाया गया है। चूंकि दहेज में लायी गयी विद्युत के लिए *** रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया गया है, इसलिए उसे *** रुपए प्रति यूनिट की विद्युत दर पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस तथ्य के बावजूद मिहाड में विद्युत के उत्पादन की लागत *** रुपए बनती है। यदि इस आंकड़े पर विचार किए जाने की आवश्यकता है तो विद्युत संयंत्र में किए गए निवेश पर प्रतिलाभ पर भी विचार/शामिल किए जाने की भी आवश्यकता है।
- (7) याचिकादाता ने *** रुपए के रूप में आर-22 के उत्पादन की लागत सूचित की है जबकि प्राधिकारी ने *** रुपए के रूप में उत्पादन की लागत को अपनाया है। प्रत्यक्षतः प्राधिकारी ने सीएएस4 के अनुसार लेखा बहियों में उल्लिखित उत्पादन की लागत को *** रुपए के आंकड़े के बतौर विचार किया है। अन्य शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने आर-22 की उत्पादन की लागत *** रुपए के आंकड़े पर विचार किया है जोकि याचिकादाता ने अपनी लेखा बहियों में उल्लिखित किया है। तथापि, प्राधिकारी का यह निवेदन है कि सीएएस4 के अनुसार आर-22 के उत्पादन की लागत का आंकड़ा *** रुपए है। इसके अतिरिक्त, सीएएस4 के अनुसार उत्पादन की यह लागत विगत अवधि अर्थात् मार्च, 2014 तक के उत्पादन की लागत पर आधारित है। इस जांच अवधि में यह उत्पादन की लागत नहीं है। चूंकि लेखा बहियों में वर्तमान अवधि के उत्पादन की लागत कभी भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए याचिकादाता ने विगत लेखाकरण वर्ष के आधार पर सीएएस4 के अनुसार उत्पादन की लागत को अपनाया है। जांच की प्रवृत्ति अवधि में अर्थात् मार्च, 2015 में जांच अवधि के लिए सीएएस4 के अनुसार उत्पादन की लागत को अपनाया गया था। इस प्रकार, यदि सीएएस4 के अनुसार उत्पादन की लागत पर विचार किया जाता है तो आर-22 की उत्पादन की लागत का सही आंकड़ा *** रुपए होगा जिसे वर्ष के मार्च महीने में लेखा बहियों में सीएएस4 की लागत के अनुसार अपनाया गया है।

च. क्षतिरहित कीमत का पुनः परिकलन :

- (1) क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ अनुबंध-3 और डीजीएडी में अनुपालन की जा रही सुसंगत पद्धति के अनुसार प्राधिकारी द्वारा कंपनी की लेखा-परीक्षित लेखा बहियों में दर्शाई गई उत्पादन की लागत पर विश्वास किया गया है। इस मामले में आर-22 को रणजीत नगर से दहेज को अंतरित कर दिया गया था, जिसका उपयोग संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया गया था। एक ही कंपनी के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उत्पाद का अंतरण, उसके उत्पादन की लागत अथवा विक्री कीमत पर ही किया जा सकता है। चूंकि कंपनी ने ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ऐसा अंतरण, उत्पादन की लागत पर किया गया था, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए नियोजित निबल अचल सम्पत्तियों पर 22% प्रतिलाभ स्वीकृत करने पर विचार किया गया है। न्यायाधिकरण के आदेश के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के सत्यापन से पता चलता है कि आर-22 की *** कि.ग्रा. की कुल मात्रा का अंतरण *** रुपए की मूल लागत पर किया गया था, जिस पर *** रुपए के उत्पाद शुल्क को लेखा बहियों में दर्शाया गया है और सेनवाट के रूप में उसका दावा किया गया है। इस प्रकार उत्पादन की औसत लागत अथवा वित्तीय बहियों के अनुसार निबल अंतरण कीमत *** रुपए प्रति कि.ग्रा. बनती है। इसके समर्थन में कंपनी ने व्यवसायिक लागत लेखाकार द्वारा अधिप्रमाणित उत्पादन की लागत के दो विवरण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें उत्पादन की लागत *** रुपए प्रति मी.टन (***) रुपए प्रति कि.ग्रा.) और *** रुपए प्रति मी.टन (***) रुपए प्रति कि.ग्रा.) दर्शाई गई है।

- (2) दहेज की वित्तीय बहियों में भिन्न मूल्य दर्शाए गए हैं, हालांकि सत्यापित कारोबार के कुछेक नमूनों ने रणजीत नगर की बहियों में दर्शाई गई उत्पादन की लागत में कोई विचलन नहीं दर्शाया है। कंपनी से अनुरोध किया गया था कि वह दिनांक 21.02.2017 के मेल में ऐसे अंतर के लिए सही कारण बताए लेकिन सत्यापन के समय उसके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका था। इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि दहेज की बहियों में पूंजीकृत मद के रूप में *** कि.ग्रा मात्रा दर्शाई गई थी, जिसके लिए कोई लागत निर्धारित नहीं की गई थी और इसलिए यदि आर-22 की *** रुपए कि.ग्रा. लागत को बाकी मात्रा की लागत के रूप में फैला दिया गया होता, तो औसत लागत अधिक होती। चूंकि सत्यापित कुछेक कारोबार की नमूना पंक्ति प्रविष्टियों से दहेज के मालसूची के खाते में प्राप्त वस्तुओं की समान मूल्य में समान मात्रा दर्शाई गई है, इसलिए उत्पादन की लागत जिस पर आर-22 को रणजीत नगर की बहियों में अंतरित किया गया था वही है। उत्पादन की उक्त लागत को लेखा बहियों, लागत लेखाकरण अभिलेखों और अन्य अभिलेखों से व्यवसायिक लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् सत्यापित लागत विवरण के आधार पर अपनाया गया था। याचिकादाता ने भी यह उल्लेख करते हुए विवरण को प्रमाणित किया है कि यह उद्योग द्वारा अपनाई जा रही सामान्य रूप से स्वीकृत लागत लेखाकरण के सिद्धांतों और पद्धतियों के अनुपालन के समनुरूप हैं। इसलिए आर-22 की उत्पादन लागत *** रुपए प्रति कि.ग्रा. अपनाई गई है।
- (3) निबल अचल सम्पत्तियों पर प्रतिलाभ के परिकलन के संबंध में कंपनी द्वारा प्रदान किए गए व्यौरों की जांच प्रायोगिक अधिशेष से तुलना करके की गई है और इन्हें सही पाया गया है। कंपनी ने *** लाख रुपए के एनएफए और दहेज को अंतरित की गई *** मी.टन की मात्रा का दावा किया है। यदि उक्त एनएफए पर 22% की दर से प्रतिलाभ स्वीकृत किया जाता है, तो कुल प्रतिलाभ और प्रति किलोग्राम प्रतिलाभ *** लाख रुपए और *** रुपए प्रति कि.ग्रा. बनता है। इसके विपरीत डीजीएडी के कार्यचालन से *** रुपए प्रति कि.ग्रा. का पता चलता है और उसी पर विचार किया गया है।
- (4) एनएफए के विस्तृत कार्यचालन की बारीकी से जांच की गई थी। इसमें दहेज से रणजीत नगर को अंतरित किए गए क्लोरोफोर्म के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया था, आर-22 और आर-22 के एनएफए के उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती पदार्थ एएचएफ का एनएफए प्रयुक्त किया गया था। समान दर के आधार पर अप्रत्यक्ष सामान्य सम्पत्तियों को भी शामिल किया गया था। कार्य-चालन में विचलन केवल क्लोरोफोर्म के एनएफए के मामले में किया गया था। वास्तव में क्लोरोफोर्म एमडीसी का एक संयुक्त उत्पाद था जिसके लिए समान जांच अवधि के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया था। एमडीसी के लिए अपनाया गया वास्तविक एनएफए, समानुपात औसत पर था। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए एनएफए में गणितकीय त्रुटि को सही कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप एनएफए पर प्रतिलाभ के दावे में परिवर्तन हो गया था।
- (5) एनएफए पर प्रतिलाभ को लागू करके आर-22 के लिए संशोधित अंतरण कीमत *** रुपए बनती है और भारित औसत दर *** रुपए प्रति कि.ग्रा. परिकलित की गई है जबकि इसकी तुलना में एनआईपी के निर्धारण के लिए पहले *** प्रति कि.ग्रा. प्रयुक्त की गई थी।
- (6) टीएफई के उत्पादन के लिए अपनाए गए खपत के मानक, टीएफई के आर-22 के लिए *** रुपए प्रति कि.ग्रा. थे। इस खपत मानक पर टीएफई के उत्पादन की लागत *** रुपए प्रति कि.ग्रा. अधिक होगी। चूंकि संबद्ध पीटीएफई के उत्पादन के लिए *** कि.ग्रा. टीपीई की आवश्यकता होती है, टीएफई की लागत में ऐसा परिवर्तन करके पीटीएफई की एनआईपी *** रुपए प्रति कि.ग्रा. पर विचार किया गया है।

प्राधिकारी ने प्रकटन के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की है और उनका यह मानना है कि:

- (1) दहेज संयंत्र में नियोजित पूंजी में पहले निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम के दौरान याचिकादाता के साथ हिस्सेदारी की थी और चूंकि याचिकादाता ने दहेज में आर-22 संपत्तियों के एनएफए के बारे में नहीं बताया है, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि इसने उसे टीएफई की संपत्तियों में पहले से ही समामेलित कर दिया है।
- (2) मिहाड में विंड मिल संपत्तियों पर प्रतिलाभ स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह एक पृथक लाभ अर्जित करने वाला केन्द्र है और यह अपनी विद्युत मै0 दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड को बेचता है।
- (3) आर-22 के उत्पादन की औसत लागत को अपनाया गया है, जैसा कि लेखाओं की वित्तीय बहियों में परिलक्षित होता है। इसलिए प्राधिकारी ने पहले से विचार नहीं किए गए एनएफए पर अतिरिक्त प्रतिलाभ

को ध्यान में रखते हुए *** रुपए प्रति कि.ग्रा. की पहले से अपनाई गई एनआईपी को संशोधित कर *** रुपए प्रति कि.ग्रा. कर दिया है (जिसमें *** रुपए प्रति कि.ग्रा. तक की वृद्धि हुई है)।

- (4) सी.ओ. की दो विभिन्न संख्याओं के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी ने उपरोक्त आगामी पैराओं में पहले ही बताया है कि ऐसी स्थिति याचिकादाता द्वारा मूल निर्णायक समीक्षा जांच की कार्रवाई के दौरान प्रकटन विवरण के विलंबित स्तर पर विभिन्न संख्याओं के बारे में सूचित करने के कारण उत्पन्न हुई है।
- (5) क्लोरोफार्म संपत्तियों पर प्रतिलाभ याचिकादाता द्वारा दावा किए गए अनुपात में एमडीसी के अनुसार प्रदान किया गया था। चूंकि ये दोनों संयुक्त उत्पाद हैं। याचिकादाता ने एमडीसी के एनएफए को कभी चुनौती नहीं दी थी।

छ. निष्कर्ष

उपरोक्त निवेदनों और मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने अनुबंध-3 में उल्लिखित अनुसार लागत पर अंतरित की गई इनपुट के मामले में कैप्टिव इनपुट के उत्पादन के लिए अपेक्षित एनएफए के समनुरूप 22 प्रतिशत का प्रतिलाभ प्रदान करने की अपनी कार्यप्रणाली को ध्यान में रखने के बाद क्षतिरहित कीमत का उचित रूप से पुनः परिकलन किया है।

ज. सिफारिशें:

प्राधिकारी सेस्टेट के दिनांक 16.9.2016 के आदेश के अनुसार पुनः परिकलित एनआईपी को ध्यान में रखते हुए कमतर शुल्क के नियम के अनुसार मौजूदा पाटनरोधी शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करने की सिफारिश करते हैं :

प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए दिनांक 6 जून, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 23/2016 द्वारा लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क में संशोधन करते हुए रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके।

तदनुसार रूस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे तालिका के कालम 9 में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है जिससे दिनांक 6 जून, 2016 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 23/2016 द्वारा लगाया गया मौजूदा पाटनरोधी शुल्क संशोधित हो जाएगा।

शुल्क तालिका

क्रमांक	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	3904 61 00	पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन (पीटीएफई)	कोई	रूस	रूस	कोई	कोई	874.56	मी.टन	अम. डालर
2.	3904 61 00	पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन (पीटीएफई)	कोई	रूस	रूस से इतर अन्य कोई	कोई	कोई	874.56	मी.टन	अम. डालर
3.	3904 61 00	पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन (पीटीएफई)	कोई	रूस तथा चीन जनवादी गणराज्यसे इतर अन्य कोई	रूस	कोई	कोई	874.56	मी.टन	अम. डालर

इस अंतिम जांच परिणाम के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2017

FINAL FINDINGS**(Anti-Dumping Investigation)**

Subject:— Anti-dumping investigation concerning imports of “Polytetrafluoroethylene” (PTFE) originating in or exported from Russia remanded by Hon’ble CESTAT through Order dated 16.09.2016.

No. 15/2/2015-DGAD.—Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules), and the Hon’ble CESTAT’s order no. 53592/2016 dated 16.09.2016

A. Background of the Case

Based on a Sunset Review petition filed by the by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd., the Authority had issued Final Finding dated 12th April, 2016 recommending imposition of AD Duty on imports of “Polytetrafluoroethylene” (PTFE) originating in or exported from Russia. DOR through Notification No 23/2016-Customs (ADD) dated 6th June 2016 levied AD Duty for a period of 5 years from the date of Notification.

Based on the domestic industry’s appeal, the Hon’ble CESTAT on the issue of NIP determination have remanded the case to the Designated Authority directing the Authority to complete determination and give Final Finding to the Competent Authority of the Government to take the action as deemed fit within a period of six months from the date of the Order i.e. 16th September, 2016 in accordance with the directions in para 9 of the aforesaid order. The revised Final Finding have therefore to be completed by 15th March, 2017.

Domestic industry has represented that Non-Injurious Price (NIP) determined by the Authority is low and inconsistent with the principles laid down in Annexure III of AD Rules and also contrary to the consistent position taken by DA while valuing inputs captively used for manufacture of subject goods since as per consistent practice, the Authority adds 22% return on capital employed for assets utilized for producing such inputs if these are transferred at cost of production.

The Domestic Industry submitted before the Tribunal that the appellant had provided detailed statement showing cost of production of these various captive inputs to DA during investigation.

CESTAT has observed that the only point of determination is correctness of method adopted by DA while arriving at NIP considering a large number of captively produced and consumed inputs while manufacturing the subject goods by the appellant. The Tribunal, further observed that DA has been adding 22% return of capital employed in producing captively inputs for arriving at NIP.

CESTAT also observed that the Authority has not recorded any reasons for such sudden change in practice, nor any reason stated for adopting Central Excise provision of Valuation (Rule 8) for captively used inputs. There is no provision in AD Rules or in Customs Tariff Act which mandates the application of such rule and to calculate NIP in AD investigation. In such a matrix, CESTAT found that NIP determined in the present case was faulty, in so far as, it relate to the treatment of captively used goods with specific reference to profit/return on capital deployed.

CESTAT therefore set aside the Final Finding dated 12th April 2016 of the Authority on this account and directed the Authority that the matter may be re-examined afresh after giving due opportunity to the interested parties to arrive at a finding in consonance with the legal provision applicable. The reason for arriving at a particular NIP with specific reference to the treatment of captively used inputs are to be recorded. Thereafter the injury margin and the AD duties liable to be imposed may be determined as per law in the present case.

B. Procedure adopted

- (i) In accordance with Rule 6(6) of the Rules and CESTAT’s order dated 16th September 2016, the Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 2nd December, 2016. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views for mutual exchange with opposing interested parties for filing rejoinders thereafter by others.
- (ii) The petitioner filed response giving details of cost of production of R-22 at Ranjit Nagar and the net fixed assets deployed for its production vide letter dated 11th January 2017, *stating that the data submitted may have error in*

calculations and therefore, the same is being reviewed. It further stated that rules require the Authority to consider actual cost of production of captive input and not at NIP of captive inputs.

- (iii) The data submitted by the petitioner in DGAD was verified on 23rd February 2017, as made available.
- (iv) *** in this final finding represents information furnished by an interested party/any other party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (v) In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 8th March, 2017 to the concerned interested parties. Comments were requested by 14th March, 2017. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority have been considered in this final finding.
- (vi) All other parameters related to the Product Under Consideration, scope of Domestic Industry, Period of Investigation, dumping and injury assessment remain the same. The findings are limited to determination of NIP only as the remand by Hon'ble CESTAT is on issue of redetermination of NIP only.

C. Submissions made by various Interested Parties

a. Submissions by Exporter M/s World Trade Consultants & Advocates representing OAO HaloPolymer OJSC, Russian Federation

- i) The appeal before the Hon'ble Tribunal has been based on the premise that the Designated Authority has been consistently adopting cost of production of the captively produced raw materials and add 22% Return on Capital Employed to such raw material cost to work out the Non-injurious price for the finished product and the Non-injurious price determined in the Final Findings under appeal has not been worked out on the same basis. Based on such argument, the Hon'ble Tribunal set aside the Final Findings and asked to the Designated Authority to reconsider the whole issue. The argument of the Domestic Industry that the Designated Authority has been consistently applying 22% return on capital employed in case of captively produced raw materials appears to be misleading and not based on facts. In the last Sunset Review Investigation concluded vide Final Findings No. 15/30/2008-DGAD, dated 26th February 2010, in respect of PTFE from Russia, it can be inferred from the para 23 that the Designated Authority did not adopt 22% ROCE in respect of captively produced and consumed raw material- R 22 to arrive at the Non-injurious price of PTFE. The Domestic Industry has wrongly submitted before the Hon'ble Tribunal that it has been a consistent practice of the Designated Authority to add 22% of ROCE to the cost of production of captively produced raw materials to arrive at the Non-Injurious Price of the finished products. The claims of the Domestic Industry in the current investigation about transfer price of R 22 are entirely different from its claims in the last SSR concluded in 2010. It is stated that the Domestic industry's claim of providing 22% ROCE on R22 in last SSR is therefore false.
- ii) The Designated Authority shall distinguish between captive consumption of raw material produced at different location and moved to another location for captive consumption and raw material produced and consumed at the same location.
- iii) The Captive Consumption has been defined in chapter 1 of the guidance note on Cost Accounting Standard on Cost of Production for Captive Consumption (CAS-4). The Institute of Cost & Works Accountants of India has also classified captive consumption into two categories, namely –
 - a. Raw materials produced in the same factory premises and used for captive consumption, and
 - b. Raw materials produced by the same company but at different factory/location and moved to another factory for captive consumption for further production of different product.
- iv) The Institute has prescribed different treatment for both the type of captive consumption. In case the raw material used is manufactured in the same factory premises the same must be valued at cost and in case the raw material is moved from one factory premises to another factory premises for captive consumption, the same must be valued by adopting principles laid down under CAS-4. In the instant case R 22 is captively produced at Ranjit Nagar plant of Gujrat Fluorochemicals Ltd., and then moved to Dahej plant for captive consumption to manufacture PTFE.
- v) For goods manufactured, not sold but captively consumed the cost of production is to be determined as per CAS-4 vide Government of India, Ministry of Finance & Company Affairs (Department of Revenue's Circular dated 13th February, 2003. As per chapter-3 of Principles of determination of cost of production for captive consumption issued by the Institute of Cost & Works Accountants of India, for the self-manufactured items, Circular No. 692/08/2003-CX 13th February, 2003, F.No.6/29/2002-CX.I, Ministry of Finance and Company Affairs, Department of Revenue states that the cost of production of captively consumed goods will henceforth be done strictly in accordance with CAS-4.

- vi) The cost of production for captively consumed goods is to be determined as per CAS-4, in light of Supreme Court's judgment dated 1.8.2006 in case No. Appeal (civil) 2947-2948 of 2001 Commissioner of Central Excise, Pune vs M/s Cadbury India Ltd.
- vii) The Designated Authority has rightly worked out the transfer price of R 22 used captively for manufacture of PTFE by Gujrat Fluorochemicals Ltd., in accordance with guidelines issued by the Institute of Cost & Works Accountants of India.

b. Submissions by Domestic Industry

- (i) Petitioner considers that there was no need for granting oral hearing in the present case. The CESTAT has not directed holding of oral hearing in the present case. When the CESTAT wished the Designated Authority to hear the interested parties, the same was specifically stated by the CESTAT. In the decision of the CESTAT in the matter of rubber chemicals, wherein the CESTAT had remanded the case back to the Designated Authority it had specifically directed the Designated Authority to hear the interested parties.
- (ii) The limited issue in the present case concerns only one aspect of NIP determination. The Petitioner domestic industry had requested the Designated Authority to consider captive input at its cost of production and add 22% return on capital employed. CESTAT has held that the Designated Authority is required to add 22% return on capital employed.
- (iii) The only limited issue to be considered in the present case is to modify the NIP earlier determined by adding 22% return on the capital employed. All other aspects of NIP determination have already been frozen by the Designated Authority and the domestic industry or other interested parties have not raised any concern about the same.
- (iv) In a remand back proceedings, the Designated Authority is not required to undertake fresh determination. The Designated Authority is required to only address the issue raised by the party and decided by the CESTAT. The only issue raised by the domestic industry was that the NIP should be determined after adding 22% ROCE to the captive inputs. No other aspects of NIP are required to be revisited at this stage.
- (v) The CESTAT has held that Excise Valuation is not relevant for the present purposes.
- (vi) As regards contention of one interested party that the DI submitted, without any basis, before the Hon'ble Tribunal that it has been a consistent practice of DA to add 22% of ROCE to the cost of production of captively produced raw materials to arrive at the NIP of the finished products tantamount to challenging correctness or otherwise of the decision of the CESTAT. Firstly, the party preferred not to participate in the appeal before CESTAT despite being made a respondent. Secondly, scope of the present proceedings is not to review the correctness or otherwise of the order of CESTAT. If an interested party does not agree with the CESTAT order, it is open for such party to prefer an appeal against the order before higher courts. The DA however is not required to consider the correctness or otherwise of the order of the CESTAT. The DA is required to determine the NIP and injury margin having regard to the order of the CESTAT, which clearly states that the DA shall consider R-22 at its cost of production and add 22% return thereon. Barring the very limited issue of (a) adding 22% return on capital employed in R-22 value, (b) determining NIP thereafter and (c) calculating revised injury margin, nothing else is required to be re-done in the present remand proceedings. The DA may therefore not entertain any argument with regard to appropriateness or otherwise of the CESTAT order.
- (vii) The domestic industry submits that it is not open for the parties to challenge the correctness or otherwise of CESTAT order before Designated Authority. The interested parties have no locus standi as it was open for the parties to challenge the appeal filed by the domestic industry before CESTAT and defend their interest and/or DA's order. Now that the CESTAT has passed an order, the interested parties cannot sit on the judgment of CESTAT and contend anything with regard to correctness or otherwise of the CESTAT order.
- (viii) As regards (CAS-4) and the Supreme Court's judgment mentioned by an interested party is concerned, the same has absolutely no relevance to the present investigation. For the present purposes, as held by the CESTAT, the Govt. has formulated a methodology and has introduced a law and the same is required to be applied. The law does not state that captive input shall invariably be considered at its cost of production. All decisions referred by the interested party relates to excise cases which have no relevance to the present issue. In fact, the CESTAT has already held that excise valuation and the methodology applied therein is entirely irrelevant for the present purposes.
 - a. On the issue that the DA shall distinguish between captive consumption of raw materials produced at different location and moved to another location for captive consumption and raw material produced and consumed at the same location there is no scope with the parties to argue against CESTAT order. CESTAT order cannot be construed to imply two different methodologies. On the contrary, the CESTAT has clearly held that the excise methodology shall not be considered for the present purposes.

- (ix) In the light of the orders of the CESTAT and information earlier provided Petitioner requests the Designated Authority is not required to consider the correctness or otherwise of the order of the CESTAT should add 22% to the captive inputs and modify the NIP appropriately and modify injury margin appropriately considering revised/modified NIP and recommend upward revision/enhancement of the quantum of anti-dumping duty.

C. Submissions by the Ministry of Economic Development of the Russian Federation

- (i) The requested revision of the Final Findings has to be in full compliance with the Agreement of implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade 1994 WTO (the Anti-dumping agreement) and conclusions of the Directorate General, and be outside the framework of calculation of Non-Injurious Price in the course of the revision.
- (ii) According to Article 10 of the Custom, Excise and Gold (control) Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982 and that in the frame of the Customs Excise & Services Appellate Tribunal the calculation of the Dumping Margin, the Injury Margin done by the Directorate General should not be revised.
- (iii) Calculation of non-injurious price itself is not essential and is not prescribed by the Anti-dumping agreement. Universal practice to apply Anti-dumping measures shows that in the most cases a rate of duty corresponds to an Injury Margin determined during the course of an investigation.
- (iv) According to WTO's Rules calculation of non-Injurious price in the frame of Anti-dumping investigation is a realization of Lesser Duty Rule, implicating the imposition of an Anti-dumping duty at the rate sufficient to remove the Injury to the Domestic Industry. This methodology is a tool of securing of the state economic interests, understood in this case, as ensuring a balance between the injury to the Indian domestic industry and possible consequences to the consumers of the imported goods. Those calculations and analyse shall be conducted by the competent body, Authorized to conduct such Anti-dumping investigation.
- (v) Under clause 9.1 of the Anti-dumping agreement, the decision whether or not to impose an Anti-dumping duty in cases where all requirements for the imposition have been fulfilled, and the decision whether the amount of the Anti-dumping duty to be imposed shall be the full margin of dumping or less, are decisions to be made by the Authorities of the importing Member. It is desirable that the imposition be permissive in the territory of all Members, and that the duty be less than the margin if such lesser duty would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
- (vi) The Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties as the competent Authority is authorized to make a decision concerning the rate of the Anti-Dumping duty using calculation of the non-injurious price in order to ensure a balance between interests of the importers and the producers.
- (vii) Besides, according to the document of the Customs Excise & Services Appellate Tribunal, the appellant considers that the Non-Injurious Price determined by the Directorate General is incorrect, with the unreasonably used methodology other than applicable during the previous investigations.
- (viii) Notwithstanding the Indian Anti-dumping legislation contains as an appendix an approximate methodology of calculation of non-injurious price, it does not state an obligation of the competent body to use one or another methodology. Therefore, the Indian Anti-dumping does not suppose the Directorate General to prove a choice of a methodology to calculate non-injurious price for the purpose of implementation of the lesser duty Rule.
- (ix) We express our concerns regarding intentions of the Indian side to re-count of the rate of Anti-dumping duty stipulated in the article 8 of the Customs Excise & Services Appellate Tribunal's statement and that the Russian exporters shall not bear responsibility for the incorrectness methodology (from the point of view of the Appellant), chosen by a competent body in the course of review of the Anti-dumping duty.
- (x) The claim of the Appellant could lead to the breach of the Anti-dumping legislation by the Indian side.
- (xi) If such modification of the non-injurious prices is done, it should, taking into account of the lesser duty rule, then the amount of price underselling and price undercutting, calculated for the Russian companies during the course of the revision, be complied with.

D. Facts of the Case and re-examination of NIP

- (i) The petitioner M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. is having two plants –one in Ranjit Nagar and the other at Dahej. During POI, one of the key inputs R- 22 produced in Ranjit Nagar was used in its Dahej Plant for the production of TFE. TFE is the key raw material for the production of subject goods PTFE. Both the plants are multi-product and multi-process plants.
- (ii) The petitioner in its original SSR petition did not provide cost of production including details of assets deployed for the production of R-22 at its Ranjit Nagar Plant. Also during on the spot verification, such data was not provided by the company. As petitioner did not claim price of R-22 at cost of production plus 22% return on capital employed, the value of R-22 was considered as per their books of accounts.

- (iii) Rule 8 of Central Excise Valuation (Determination of price of excisable goods) Rule 2000 provides that where the excisable goods are not sold by the assessee but are used for consumption by him or on his behalf in the production or manufacture of other articles, the value shall be one hundred and ten per cent of the cost of production or manufacture of such goods. CAS 4 is the guidance note issued by the Institute of Cost Accountants of India stating that this Standard lay down the principles and methods for determining the cost of production of excisable goods used for captive consumption, presentation and disclosure in the cost sheet. This Guidance Note further states that “cost of production of captively consumed goods will henceforth be done strictly in accordance with CAS-4”. This Standard lays down the principles for determination of cost of production on which 10% element of profit will be added to arrive at assessable value for the purpose of invoice value of inputs removed for the purpose of consumption by another unit of the assessee.
- (iv) Since the petitioner did not claim price of R-22 and did not provide necessary details neither at the stage of submission of petition nor at the time of on-the spot verification, it was understood that the company is following CAS-4 and Central Excise Valuation Rules for determination of transfer price of R-22. The Authority on its own could not have estimated cost of production and value of assets deployed for the production of captive input R-22 and had to rely on books of accounts. Clause (3) of Annexure III also provide for determination of NIP by considering the information or data relating to cost of production for the period of investigation in respect of the producer constituting domestic industry and cost of production comprise real numbers as shown in the audited books of accounts not the notional or imaginary numbers. It does not state that the Authority on its own should construct the cost of production of constituent domestic industry without any cost data being provided by the Domestic Industry.
- (v) This issue was raised by the representative of the petitioner vide letter dated 31.03.2016 for the first time requesting for additional return on wind power assets and assets deployed for producing R-22 at Ranjit Nagar. The Domestic Industry’s representative categorically stated that while reviewing the costing of MDC another case of the same company going simultaneously in DGAD, the petitioner found that information in regard of capital deployed for production of captively input at other location was not provided inadvertently.
- (vi) The petitioner was given due opportunity to provide duly substantiated and certified details/documents relating to cost of production of R-22 but they failed to provide the same. Therefore, in the absence of duly certified and substantiated cost information it was not possible for the Authority to consider their claim without verification. Moreover, ***% profit was already in-built (assuming the company had not violated the Excise Valuation Rules) in lieu of 22% return on capital deployed for the production of R-22 at its Ranjit Nagar plant. The practice in DGAD to accept the transfer price as per excise valuation rules has been followed earlier in number of cases including this case during earlier investigations, and such a practice has never been raised or challenged by the petitioner or other Domestic Industry in any case in the past. The Authority notes that in the following previous PTFE cases the appellant did not raise any objection:
 - SSR investigation relating to import from Russia (F. No. 15/30/2008-DGAD)- The position taken by the Authority vide Para 23 (d) of Final Finding dated 26th February 2010 was “.....since the domestic industry is captively producing R-22, the Authority is required to consider market price of R-22. The cost of production of R-22 is therefore, in any case not relevant for determination of NIP of PTFE”
 - SSR case for imports from China. (F. No. 15/8/2010-DGAD). The position taken by the Authority vide Para 29 (iii) of Final Finding dated 25th July 2011 was “.....With regard to the issue of transfer pricing of R-22 on the basis of GAPP and based on records maintained by the companies.
 - Similar position taken was during MTR finding vide para 29 (c) “...the Authority is required to consider market price of R-22. The cost of production of R-22 is therefore, in any case not relevant for determination of NIP of PTFE.”

E. Response to the disclosure

Domestic industry in response to the disclosure has made the following submissions

- (i) The disclosure statement does not enable the petitioner to fully understand amounts adopted by the authority, not accepted and accepted. In the absence of complete disclosure, petitioner is unable to fully comprehend the calculations done by the authority, methodology applied for determination of revised NIP and elements of costs and capital employed accepted and elements of costs and capital employed rejected.
- (ii) The Authority had earlier verified cost of production of R22 at the time of sunset review investigations and the same has now been revised. This implies that the authority has considered two different cost of production for R22 – one at the time of sunset review investigations and another now. Since the cost of production of R22 was already verified at the time of sunset review, the same was not required to be revisited. There is no justification for the modification to the R22 cost of production carried out now.

- (iii) The petitioner has provided each and every information demanded by the DGAD and there is no communication to the petitioner prior to the present disclosure statement stating therein that the petitioner has not provided some information or some clarification sought could not be given either in writing. Petitioner considers that it is inappropriate to hold that during the verification no satisfactory reply could be furnished.
- (iv) The NFA for chloroform has been taken without doing averaging of the opening and closing NFA. Only opening NFA figure has been considered. Closing NFA appears to have been ignored. If so, petitioner submits that it is Authority's consistent practice to consider average NFA by doing simple averaging of opening and closing NFA.
- (v) Petitioner submits that the NIP determined does not include capital employed in Dahej amounting to Rs. *** which is the capital employed in production of R22 and all its captive inputs in Dahej. Since a portion of R22 has been produced and consumed in Dahej, the capital employed in R22 and all its inputs produced and consumed in Dahej itself is required to be considered. This amount is clearly shown in the NFA schedule of Dahej plant. Further, this amount was also clearly reported in the information filed in MDC case.
- (vi) The NIP has been determined considering wind mill power rate as Rs. ** per unit. This figure is not correct. The figure of Rs. ** is the cost of production of power at Mihad wind mill plant and is shown in the books of Ranjit Nagar. All this power is consumed in Dahej. This power is however given by the company to the Govt. at Mihad @ Rs. ** and bought at Dahej @ Rs. ** per unit (Rs. ** tfd cost and Rs. ** Wheeling Charges). The company has paid for this power at Dahej at the rate of Rs. ** per unit in the books of Dahej. Since the power brought at Dahej has been paid @ Rs. ** per unit, the power rate that is required to be considered as Rs. ** per unit. Notwithstanding, the figure of Rs. ** in any case is cost of production of power at Mihad, if this figure is required to be considered, then return on investment made in power plant is also required to be considered/included.
- (vii) The petitioner has reported the cost of production R22 as Rs. **, whereas the authority has adopted Rs. ** as the cost of production. Apparently, authority has considered that the figure of Rs. ** is the cost of production reported in the books as per CAS4. In other words, authority appears to have considered figure of Rs. ** as the cost of production of R22 considered by petitioner in its books. Petitioner however submits that the figure of Rs. ** is the cost of production of R22 as per CAS4. Further, this cost of production as per CAS4 is based on cost of production of previous period i.e. till Mar' 14. This is not cost of production in the investigation period. In books of accounts, since cost of production for the current period is never available, the petitioner adopts cost of production as per CAS4 on the basis of previous accounting year. The cost of production as per CAS4 for the investigation period was adopted in the period subsequent to the investigation period i.e. March, 2015. Thus, if CAS4 cost of production is to be considered a cost of production of R22, the right figure is Rs. **, which has been adopted as CAS4 cost in the books for the year March.

F. Recomputation of the Non-Injurious Price

- (i) In terms of Annexure III and the consistent practice being followed by the Authority, the cost of production as shown in the audited books of accounts has to be relied upon for the purpose of determination of NIP. In this case, R-22 was transferred from Ranjit Nagar to Dahej which was used for the production of subject goods. The transfer from one unit to another of the same company can be made at cost of production or at selling price. Since the company has evidenced that the transfer was made at cost of production, a return @ 22 % on net fixed assets deployed for the production of subject goods is considered. The verification of data submitted post Tribunal orders show that total quantity of *** kg of R-22 was transferred at basic cost of Rs. *** on which excise of Rs. *** was shown in the books and claimed as CENVAT. Thereby, average cost of production or net transfer price as per financial books works out Rs. *** per kg. In support, the company furnished two statements of cost of production certified by a practising cost accountant stating the cost of production of Rs. *** per MT (Rs. *** per kg) and Rs. *** per MT (or Rs. *** per kg).
- (ii) The financial books of Dahej showed different values, though the line entries of some of the sample transactions verified did not show any deviation from the cost of production shown in Ranjit Nagar books. The company was requested to give cogent reasons for such variation in the mail dated 21/02/2017 but during the verification no satisfactory reply could be furnished. The main reason could be that a quantity of *** kg was shown in the books of Dahej as capitalized item for which no cost was assigned, and therefore the average cost would be higher if the cost of *** kg R-22 was spread on the cost of remaining quantity. Since, the sample line entries of some of the transactions verified showed the same quantity of goods received in the inventory ledger of Dahej at same value, the cost of production on which R-22 was transferred in the books of Ranjit Nagar. The said cost of production was adopted on the basis of cost statement duly verified by a practising cost accountant from the books of account, cost accounting records and other records. The petitioner had also certified the statement saying that it was in compliance with

generally accepted cost accounting principles and practices followed by the industry. Therefore, the cost of production of R-22 has been adopted at Rs. *** per kg.

- (iii) As regards computation of return on net fixed assets, the details provided by the company were test checked from the trial balance and found to be in order. The company had claimed NFA of Rs *** lacs and volume of *** MT transferred to Dahej. If return is allowed @ 22% on the said NFA, the total return and per kg return works out to Rs. *** lacs and Rs *** per kg. As against this, DGAD working shows the return as Rs. *** per kg and the same has been considered.
- (iv) The detailed working of NFA was thoroughly examined. It included the NFA of chlorine, used for production of chloroform, Chloroform itself which was transferred from Dahej to Ranjit Nagar, NFA of AHF the intermediate used in the production of R-22 and NFA of R-22. The indirect common assets were also included on pro rata basis. The only deviation in the working was made in the case of NFA of chloroform. In fact, chloroform was a joint product with MDC for which NIP was determined by the Authority for the same POI. The actual NFA adopted for MDC was adopted in appropriate ratio claimed by the petitioner. The arithmetic error in the NFA submitted by the Domestic Industry was corrected leading to change in the claim of return on NFA.
- (v) By applying the return on NFA, the revised transfer price of R-22 works out to Rs. *** and weighted average rate has been computed at Rs *** per kg against Rs *** per kg used earlier in the determination of NIP.
- (vi) The consumption norms adopted for the production of TFE was *** kg of R-22 per kg of TFE. At this consumption norm the cost of production of TFE will be higher by Rs. *** per kg. As *** kg of TFE is required for production of subject PTFE, by applying the change in cost of TFE, NIP of PTFE is considered as Rs. *** per kg.

The Authority has examined the issues raised by the Domestic Industry in response to the disclosure and holds that;

- (i) The capital employed at Dahej Plant was duly shared with the petitioner during the earlier SSR findings and since the petitioner had not stated NFA of R22 assets at Dahej, implying that it has already been subsumed in the assets of TFE.
- (ii) The return on wind mill assets at Mihad is not admissible as it is a separate profit centre and sells its power to Dakshin Gujarat Viz Company Limited.
- (iii) The average cost of production of R22 has been adopted as reflected in the financial books of accounts. The Authority has therefore modified the NIP to Rs. *** per Kg as against earlier approved NIP of Rs. *** per kg (Increased by Rs. *** per kg) in view of additional return on NFA not considered earlier.
- (iv) As regards the issue of two different numbers of COP, the Authority has already stated in the foregoing para that such a situation arose due to petitioner's reporting of different numbers at the belated stage of disclosure during the course of original SSR investigation.
- (v) The return on chloroform assets was provided in accordance with that of MDC in proportion claimed by the petitioner since both are joint products. NFA of MDC was never challenged by the petitioner.

G. Conclusions

The Authority in view of the aforesaid submissions and evaluation has recomputed the NIP appropriately after taking into account the methodology of providing 22% return on corresponding NFA required for production of captive inputs in case those inputs were transferred at cost in terms of Annexure-III.

H. Recommendations

The Authority keeping in view of the recomputed NIP in accordance with CESTAT's order dated 16/9/2016 consequently recommends revision of the existing ADD in accordance with the Lesser Duty Rule as under:

Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends modification of the existing ADD imposed vide Customs Notification No. 23/2016 dated 6th June, 2016. Anti-dumping duty to a quantum equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, on the imports of the subject goods, originating in or exported from Russia so as to remove the injury to the domestic industry.

Accordingly, the Anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 9 of the table below is now recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from Russia, thereby modifying the ADD imposed vide Custom Notification No. 23/2016 dated 6th June, 2016.

DUTY TABLE

Sl. No.	Tariff Item	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	3904 61 00	Polytetrafluor-oethylene (PTFE)	Any	Russia	Russia	Any	Any	874.56	MT	US Dollar
2.	3904 61 00	Polytetrafluor-oethylene (PTFE)	Any	Russia	Any other than Russia	Any	Any	874.56	MT	US Dollar
3.	3904 61 00	Polytetrafluor-oethylene (PTFE)	Any	Any other than Russia or People's Republic of China	Russia	Any	Any	874.56	MT	US Dollar

An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

Dr. INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority